

- (२) विशेष मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में किताबों की छुपाई तथा दस्तावेजों के अनुवाद को स्थगित कर दिया जाना;
- (३) रजिस्ट्रार को प्ररीतियों की स्वीकार करने के लिये आदेश देने का अधिकार दे दिया जाना और
- (४) मूल व्यवहारवाद में प्रथम अपील के सम्बन्ध में जिला-न्यायाधीशों का आर्थिक अधिकार ५,००० रु० से बढ़ा कर १०,००० रु० कर दिया जाता जिसके कलम्बरूप प्रथम अपीलों का हाई कोर्ट में आने की संख्या में कमी हो जाना ।

Old System of Voting

2097. Shri Hem Raj: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) the names of the constituencies where the old system of ballot papers was continued during 1962 elections instead of the new marking system;

(b) the percentage of the invalid votes to the votes polled in the above-mentioned constituencies; and

(c) the percentage of invalid votes under the marking system?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri B. Mishra): (a) and (b). A statement showing the names of the Assembly and Parliamentary constituencies where the balloting system was continued in the 1962 elections and the percentage of votes rejected in the Assembly constituencies is laid on the Table of the House. [See Appendix III, annexure No. 35]. Information regarding the percentage of votes rejected in the Parliamentary constituencies is not available.

(c) Information regarding percentage of invalid votes both at the elections to the House of the People and to State Legislative Assemblies under the marking system has not yet been compiled.

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापन-शुल्क

२०६८. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक, दिल्ली के अधीन स्कूलों के उन विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता की आय ५,००० रुपये प्रति वर्ष से अधिक होती है, अधिक अध्यापन-शुल्क देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह ५,००० रु० की सीमा उन समय निर्धारित की गई थी जब जीवनयापन व्यय इस समय से बहुत कम था ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि जीवनयापन व्यय के बहुत बढ़ जाने के कारण नियत आय वाले लोगों को ऊपर के भाग (क) में निरिष्ट अधिक दर अनुसार अध्यापन शुल्क देना बहुत अश्वरता है

(घ) यदि ऊपर के भाग (क) में (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या ५,००० रुपये की सीमा बढ़ायी जा रही है और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):

(क) जी हाँ ।

(ख) यह सीमा १९६३ में निर्धारित की गई थी ।

(ग) सरकार के पास पैसा काटे शिकायत नहीं आई है ।

(घ) तथा (ङ) नियम विचाराधीन है ।

Seizure of Coffee at Colbatore

2099. Shri Manlyangadan: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large stock of cured coffee found unaccounted for in curing establishment at